Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

फरवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मज़बूत करने के लिये 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति 3
- प्रदेश में स्थापित होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इंसर्जेंसी 3
- शिक्षा विभाग की नियमावली का विमोचन 4
- कोचिंग संस्थाओं में विद्यार्थियों को मिलेगी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी 4
- उद्योग मंत्री ने किया उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण 4
- निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ होगा सहकारी समितियों का गठन 5
- भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा 'कैंसर जाँच आपके द्वार' अभियान की हुई शुरुआत 5
- नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क 6
- अफ्रीकन स्वाइन फीवर संक्रमित एवं निगरानी क्षेत्र के प्रत्येक ज़िले में ब्लॉक स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल गठित 6
- "H_5N_1" एवियन इन्फ्लूएंजा 7
- चित्तौड़गढ़ ज़िले के पहले मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन 7
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की दी स्वीकृति 8
- राजस्थान डेल्फिक खेलों की आर्ट कैंप एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी से हुई शुरुआत 8
- उष्ट्र संरक्षण योजना के आवेदन हेतु बनाए गए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण 9
- राजस्थान बजट 2023-24 9
- प्रधानमंत्री ने किया दौसा, राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के प्रथम चरण का लोकार्पण 10
- डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का हुआ समापन 11
- जयपुर में बनेगा 'हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर' 11
- श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ 12
- 'साल एक : फैसले अनेक' पुस्तिका का विमोचन 12
- राज्य भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का होगा गठन 13
- सांभर फेस्टिवल-2023 13
- राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित 14
- नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं श्री सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित 14
- जयपुर के मशहूर सिटी पार्क में होगा 'रोज शो-2023' का आयोजन 15
- प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित 15
- राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-3 का शिलान्यास 15
- मुख्यमंत्री ने किया व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण 16
- पवन अरोड़ा 'विजनरी लीडर' और 'ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीरडरशिप' अवार्ड से सम्मानित 16
- राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की नई वेबसाइट लांच 17
- सीकर के दरीबा में बेसमेटल व हनुमानगढ़ के सतीपुरा क्षेत्र में मिले पोटाश के भंडार 17
- जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एमओयू पर किये गए हस्ताक्षर 17
- राष्ट्रपति ने राजस्थान के मूकाभिनय कलाकार विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित 18
- शहरों में रोज़गार गारंटी योजना का बढ़ा दायरा 18
- विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकारों एवं योजनाओं की जाँच हेतु स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान शुरू 19
- राजस्थान को मिला बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवॉर्ड 20
- 'रोज़ शो-2023' 20
- 'रोज़ शो-2023' 21

नोट :

राजस्थान

प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मज़बूत करने के लिये 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को सुदृढ़ करने के लिये 99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) प्रदेश के राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने एवं नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा।
- इसके अलावा ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
- हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला गया है। रोड सेफ्टी एक्ट के तहत राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी का गठन भी प्रस्तावित है।
- आईटीएमएस के अंतर्गत स्वचालित ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, रेड लाइट वॉयलेशन सिस्टम, विभिन्न प्रतीक चिन्ह, सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर एवं ई-चालान सहित विभिन्न कार्य होंगे।
- आईटीएमएस के प्रमुख उद्देश्यों में चालानों का समयबद्ध एवं दक्षता के साथ निस्तारण, गंभीर सड़क हादसों पर अंकुश लगाना तथा बेहतर कार्यप्रणाली के लिये राज्य के विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना शामिल हैं।

प्रदेश में स्थापित होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इंसर्जेंसी

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के क्रम में प्रदेश में अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इंसर्जेंसी और उपकरणों के लिये 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज/आयुक्तालय स्तरीय तथा ज़िला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी। लैब में राज्य के लिये साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिये विभिन्न राज्य तथा देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
- सेंटर की स्थापना से नए-नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किये जाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, साइबर क्राइम के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिये राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी ज़िलों में साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है। इन थानों में अपराधों के अनुसंधान के लिये आवश्यक उपकरण भी प्रदान किये जा चुके हैं।

नोट :

शिक्षा विभाग की नियमावली का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को राजस्थान के स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने जयपुर के शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली, 2021 का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की नियमावली का पूर्व में वर्ष 1997 में विमोचन किया गया था।
- स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली,1997 को अब पर्याप्त संशोधन एवं अद्यतन नियमों के साथ पुन: प्रकाशित किया गया है।
- उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली, 2021 में राजस्थान राज्य शिक्षा नीति समिति के तत्वावधान में निर्दिष्ट 508 पृष्ठ की नियमावली में 17 अध्यायों में समस्त सेवा नियमों, विभागीय संरचना आदि को संकलित किया गया है।

कोचिंग संस्थाओं में विद्यार्थियों को मिलेगी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी

चर्चा में क्यों ?

1 फरवरी, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, सुजस मोबाइल एप तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किये जा रहे प्रचार-प्रसार की जानकारी युवाओं तक पहुँचाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये 2 से 9 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निर्देशानुसार यह अभियान संचालित किया जाएगा।
- इसके लिये दो टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें विभिन्न कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजों में पहुँचकर राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देंगी।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इन कोचिंग संस्थानों में सुजस मोबाइल ऐप, सुजस ई-बुलेटिन, वीडियो बुलेटिन तथा सुजस आवाज के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
- विभाग की इस अभिनव पहल से न केवल विद्यार्थियों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, बल्कि आमजन तक सरकार कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुँचेगा।

उद्योग मंत्री ने किया उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

1 फरवरी, 2023 को राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल एवं संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किया। नवीन इंडस्ट्रीज सेक्टर पोर्टल के साथ ही इस सेक्टर के सभी 15 विभागों की वेबसाइट का निर्माण WebMyWay फ्रेमवर्क द्वारा किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि नवीन इंडस्ट्रीज सेक्टर पोर्टल पर उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित 15 विभागों की जानकारी एक साथ प्रदर्शित की गई है।
- इस पोर्टल में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं, फ्लेगशिप योजनाओं, सेवाओं, परियोजनाओं, राजकीय दस्तावेज़ों एवं कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी शामिल हैं।

नोट :

- सेक्टर पोर्टल को मुख्यमंत्री सूचना तंत्र से जोड़ा गया है, जहाँ से राज्य सरकार की बजट घोषणाएँ, मुख्यमंत्री की घोषणाएँ, केबिनेट निर्णय एवं जन घोषणा पत्र एवं उनकी अनुपालना की जानकारी आमजन के लिये प्रदर्शित की गई है।
- उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में विभागों की उपलब्धियों एवं नवाचारों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। क्षेत्र से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियाँ, नवीनतम अपडेट्स एवं निविदाओं की जानकारी भी सेक्टर पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है।
- WebMyWay फ्रेमवर्क से निर्मित सभी वेबसाईट समरूप होती है एवं इसमें सूचनाओं का इंद्राज केवल एक बार किया जाता है एवं उसी सूचना को अलग-अलग पोर्टल पर आवश्यकतानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है।

निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ होगा सहकारी समितियों का गठन

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जो ग्राम पंचायत न्यूनतम सदस्य संख्या 300 सहित अन्य मापदंड पूरा करेगी और हिस्सा राशि 3 लाख रुपए जमा करा देगी, वहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी.एस.एस.) का गठन प्राथमिकता के साथ कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन का प्रयास किया जाता है। जी.एस.एस. के गठन के निर्धारित मानदंड न्यूनतम सदस्य संख्या 300, हिस्सा राशि 3 लाख रुपए, अमानत राशि 1 लाख रुपए एवं 75 हज़ार रुपए लेम्प्स हेतु है।
- उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा ज़िला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।
- सहकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल 71 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 38 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना शेष है।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत आगामी 2 वर्षों में राज्य की 4171 शेष ग्राम पंचायतों में नई जीएसएस का गठन किया जाएगा। इस घोषणा के तहत विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की शेष ग्राम पंचायतों में भी नई जी.एस.एस स्थापित की जाएगी।

भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा 'कैंसर जाँच आपके द्वार' अभियान की हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि प्रदेश के जयपुर में स्थित भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा 'कैंसर जाँच आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय के ट्रस्टी, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ ने विशेष बस तैयार कर प्रदेश के गाँव-गाँव तक पहुँचकर कैंसर जागरूकता और जाँच के लिये यह पहल की है।
- कलराज मिश्र ने बताया कि गाँव में रहने वाले लोगों को इलाज और जाँच के लिये शहर आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह अभियान निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
- भगवान महावीर अस्पताल के अध्यक्ष नवरतन कोठारी और उपाध्यक्ष अनिला कोठारी ने 'कैंसर जाँच आपके द्वार' अभियान की पहल के बारे में बताया कि भविष्य में जाँच सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लिये बसों का और विस्तार किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि चिकित्सालय द्वारा प्रारंभ किये गए विशेष बस में मेमोग्राफी, एक्सरे मशीन और ब्लड जाँच उपकरण के साथ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है।

नोट :

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क

चर्चा में क्यों ?

5 फरवरी, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक लिये हुए स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- परंपरागत कला संस्कृति से सराबोर बीकानेर हाउस को राजधानी में कल्चरल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाते हुए इसके परिसर में स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि इंडिया आर्ट फेयर के दौरान इस स्कल्पचर पार्क की नींव रखी गई। बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क की शुरूआत के साथ ही कला, साहित्य, संस्कृति और विरासत से जुड़े मुद्दों पर प्रतिष्ठित हस्तियों के सान्निध्य में 'बीकानेर हाउस डायलॉग्स'का आरंभ होना एक अनूठी पहल है।
- उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिये युवा कलाकारों द्वारा समकालीन कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं वरिष्ठ कलाकारों को स्कल्पचर पार्क द्वारा स्थापत्य कला को पहचानने तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मौका प्राप्त हो रहा है।
- दिल्ली में राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने बताया कि इस स्कल्पचर पार्क में नामचीन एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मूर्तिकारों ने हिस्सा लेकर इस पार्क को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है।
- आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि 'इंडिया आर्ट फेयर'और बीकानेर हाउस के तत्वावधान में युवा पीढ़ी की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है और इससे कला साहित्य के भविष्य की दिशा का निर्धारण भी हो रहा है।
- उन्होंने बताया कि यह स्कल्पचर पार्क राजस्थानी कला, संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से जोड़ेगा। पार्क के पहले एडिशन में देश-दुनिया के विख्यात और उभरते कलाकारों की कलाकृतियों/मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है।
- बीकानेर हाउस का यह स्कल्पचर पार्क राजधानी में अपनी तरह का पहला स्कल्पचर पार्क है, जो आधुनिक व समकालीन आर्ट वर्क को प्लेटफॉर्म देने के लिये मील का पत्थर साबित होगा।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर संक्रमित एवं निगरानी क्षेत्र के प्रत्येक ज़िले में ब्लॉक स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल गठित

चर्चा में क्यों ?

6 फरवरी, 2023 को राजस्थान पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र (इंफेक्टेड जोन), निगरानी क्षेत्र (सर्विलेंस ज़ोन) एवं मुक्त क्षेत्र (फ्री जोन) के आधार पर गठित इन दलों द्वारा संक्रमित एवं शूकर वंशीय पशुओं के विचरण स्थल पर पहुँचकर सर्वेक्षण कर रोग की रोकथाम एवं निदान के लिये हर-संभव कार्यवाही की जा रही है।
- गठित दलों द्वारा संक्रमित एवं मृत शूकरों के सैंपल एकत्र कर अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि के लिये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, निषाद भोपाल भिजवाए जा रहे हैं।
- डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि रोग के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को अलर्ट जारी कर शूकर वंशीय पशुओं को इस रोग से बचाने एवं पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिये प्रत्येक ज़िले के प्रभावित क्षेत्रों में रोग सर्वेक्षण, रोग निदान, प्रतिबंधित/मुक्त क्षेत्र चिन्हित कर 'क्षेत्र विशिष्ट कार्यवाही'निष्पादित की जाएगी।
- शूकर वंशीय संक्रमित पशुओं एवं संपर्क में आए अन्य शूकरों का वैज्ञानिक रीति से यूथेनाइज, क्षेत्र का विसंक्रमण, वेक्टर कंट्रोल, जैव कचरे, पशु आहार एवं अन्य कचरे आदि का निस्तारण किया जाएगा, ताकि रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

नोट :

- वहीं जंगली शूकरों में रोग प्रकोप नियंत्रण के लिये वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्यवाही की जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल (Haemorrhagic Viral) बीमारी है। इस रोग के अन्य लक्षणों में उच्च बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख में कमी, त्वचा में रक्तस्राव, डायरिया आदि शामिल हैं।
- अफ्रीकन स्वाइन फीवर पहली बार वर्ष 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था। ऐतिहासिक रूप से, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों, दक्षिण अमेरिका और कैरीबियन में संक्रमण की सूचना मिली है।
- हालाँकि वर्ष 2007 के बाद से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सूअरों में इस बीमारी की सूचना मिली है।
- इसमें मृत्यु दर लगभग 95-100% है और इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, इसलिये इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
- अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है।

"H5N1" एवियन इन्फ्लूएंजा

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान में 'H5N1' एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर एवं जयपुर ज़िले के रोग संभावित क्षेत्रों का दौरा कर सैंपल एकत्रित कर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल को सेंपल भेजे गए थे।
- ज्ञातव्य है कि है कि सर्दियों के मौसम में राज्य के कई इलाकों में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, जिसके मद्देनज़र विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के रोग की जाँच के लिये सैंपल एकत्रित किये जा रहे हैं।
- इस संबंध में संयुक्त निदेशक डॉ. रवि इसरानी ने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा विषय विशेषज्ञों के दल के साथ केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान एवं सांभर झील का दौरा कर प्रवासी पक्षियों के सैंपल एकत्रित कर निषाद, भोपाल भिजवाए गए हैं। साथ ही प्रत्येक ज़िले पर विभाग के अधिकारियों को रोग के निदान एवं नियंत्रण के लिये उचित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। अभी तक राज्य में एवियन इंफ्लुएजा का किसी भी प्रकार का मामला सामने नहीं आया है।
- विदित है कि एवियन इंफ्लूऐंजा जिसे सामान्यतया 'बर्ड फ्लू' के नाम से जाना जाता है, एक विषाणु जनित बीमारी है। यह संक्रामक रोग मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल, आदि पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। कभी-कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है।
- पक्षियों में इसके संक्रमण का पता चलने पर संक्रमित और संपर्क वाले पक्षियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाता है।

चित्तौड़गढ़ ज़िले के पहले मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी, 2023 को राजस्थान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ ज़िले के निंबाहेड़ा के फाचर अहिरान ग्राम पंचायत में वंडर सीमेंट लि. के सहयोग से ज़िले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण छात्र-छात्राओं को लाइब्रेरी एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा प्रदान करने के लिये चित्तौड़गढ़ ज़िले में 105 मिशन एकलव्य के तहत ज्ञान केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। जिसमें से 5 ज्ञान केंद्र वंडर सीमेंट के सहयोग से स्थापित किये जा रहे हैं।

नोट :

- इन केंद्रों की स्थापना से अब गाँवो में भी शहरों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सुविधाएँ विकसित होंगी। इन केंद्रों की स्थापना पर प्रत्येक लाइब्रेरी के लिये 5 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- इन केंद्रों के संचालन के लिये संबंधित सरपंच सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएँ एवं गणमान्य नागरिकों की एक समिति गठित की जाएगी।
- इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने डीएमएफटी योजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में 20 करोड़ 72 लाख रुपए के विभिन्न सड़क एवं खेल स्टेडियम का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की दी स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- इन उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिये कुल 502 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (प्रत्येक केंद्र पर एक) के पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दी गई है।
- प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों हेतु 30 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्मित होने तक वैकल्पिक रूप से अस्थायी भवनों में इनके संचालन की व्यवस्था की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों के खोले जाने से प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के साथ राजस्थान आज देश में प्रथम स्थान पर है।
- मुख्यमंत्री इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य ढाँचे को मज़बूत बनाने के लिये नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की थी।

राजस्थान डेल्फिक खेलों की आर्ट कैंप एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी से हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जवाहर कला केंद्र में डेल्फिक गेम्स की शुरुआत आर्ट कैंप के उद्घाटन से की गई। इसके बाद क्राफ्ट प्रदर्शनी में विभिन्न हस्तकलाओं का सजीव प्रदर्शन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- जवाहर कला केंद्र में आयोजित डेल्फिक खेल क्षेत्रीय स्तर पर पहली बार आयोजित हो रहे हैं। यह खेल राजस्थान की कला और संस्कृति के संरक्षण और राज्य के युवाओं को अपनी कला की पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन खेलों में राज्य के 18 से 35 साल तक के युवा में भाग ले रहे हैं।
- आर्ट कैंप में जयपुर, कानोता, लालसोट, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, मेरठ से आए पेंटिंग कलाकार और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, भारतीय शिल्प संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट एवं ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के इंस्टालेशन आर्टिस्टों ने भाग लिया।
- इसमें भारतीय शिल्प संस्थान की ओर से बनाए गए 80 फीट के डेल्फिक आर्ट वॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सहयोग से क्राफ्ट प्रदर्शनी में लाख की चूड़ियाँ बनाना, हैंडब्लॉक प्रिंटिंग, कपड़े बुनाई, चरखा चलाना और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी की स्टॉल्स लगाई गईं।
- उल्लेखनीय है कि डेल्फिक खेलों का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में हो रहा है।

नोट :

- इसमें शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत (भारतीय फिल्म संगीत के अलावा) शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी (2 श्रेणियाँ) समेत कुल छह वर्गों में आयोजित होंगे एवं प्रत्येक वर्ग के लिये नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- गौरतलब है कि राजस्थान पहला राज्य है जो क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फिक खेलों का आयोजन कर रहा है। डेल्फिक खेलों का पहला चरण ऑनलाइन था, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा 8 जनवरी, 2023 तक आवेदन किया गया। इनमें से चयनित प्रतिभागी जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण में सम्मिलित हो रहे हैं।

उष्ट्र संरक्षण योजना के आवेदन हेतु बनाए गए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत कृषि भवन जयपुर में उष्ट्र संरक्षण योजना के आवेदन हेतु बनाए गए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ऊँटों की घटती संख्या को गंभीरता से लेते हुए 'उष्ट्र संरक्षण योजना'की घोषणा पिछले बजट में की थी।
- 'उष्ट्र संरक्षण योजना'को राज्य पशु ऊँट के संवर्धन के लिये राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत ऊँट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिये टोडियों के जन्म के अवसर पर 5000-5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में पशुपालक को दी जाएगी।
- उष्ट्र संरक्षण योजना एवं वेब एप्लीकेशन में ऊँट पालक का पंजीयन, पशु चिकित्सक द्वारा ऊँटनी व टोडिये की टेगिंग तथा ज़िला स्तरीय वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान किया गया है।
- ऊँट पालक 1 नवंबर या उसके पश्चात् जन्मे टोडियों का योजना के अंतर्गत 28 फरवरी, 2023 तक पंजीयन करवा सकते हैं। यह पंजीयन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा।

राजस्थान बजट 2023-24

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य की विधानसभा में राजस्थान बजट 2023-24 प्रस्तुत किया।

प्रमुख बिंदु

राजस्थान बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है-

- 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हज़ार 988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हज़ार 883 करोड़ 68 लाख रुपए की राजस्व व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हज़ार 895 करोड़ 67 लाख रुपए अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हज़ार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 98 प्रतिशत अनुमानित है।
- इस बजट में 19 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का 'महंगाई राहत पैकेज' की घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए करने की घोषणा की।
- मनरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोज़गार गारंटी देने की घोषणा की है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम एक हज़ार रुपए प्रतिमाह पेंशन, हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वत: वृद्धि करने की घोषणा की।
- गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स कल्याण और विकास फंड की घोषणा की।

नोट :

- 'प्रियदर्शिनी डे-केयर सेंटर योजना'के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल, 500 डे-केयर सेंटर्स खोलने की घोषणा की।
- बाड़मेर में एक हज़ार 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पॉवर प्लांट लगभग 7 हज़ार 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की घोषणा की।
- राजस्थान को 'हरित प्रदेश'बनाने के लिये राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिब्लिडिंग मिशन शुरू करने की घोषणा की।
- प्रत्येक ज़िले में एक-एक लव-कुश वाटिका खोलने की घोषणा की।
- 100 करोड़ रुपए राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन व मुख्यमंत्री लोक कलाकर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की।
- कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार करोड़ रुपए किया।
- जयपुर एवं जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की।
- सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की।
- टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा।
- 2 हज़ार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की।
- जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा स्थापित करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने किया दौसा, राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के प्रथम चरण का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा ज़िले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली-दौसा-लालसोट के प्रथम खंड का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5940 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
- इसमें बांदी कुई से जयपुर तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली 67 किलोमीटर लंबी चार लेन की छोटी सड़क, लगभग 3775 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाने वाली कोटपुतली से बड़ा ओदानियो तक छह लेन की छोटी सड़क एवं लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा लालसोट- करौली खंड का दो लेन पेव्ड शोल्डर शामिल है।
- गौरतलब है कि दिल्ली-दौसा-लालसोट राजमार्ग के निर्माण से दिल्ली और जयपुर तक की यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रामीण हाट स्थापित किये जा रहे हैं, जो स्थानीय किसानों और कारीगरों की मदद करेंगे।
- इस खंड के प्रारंभ होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा और इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे 'सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और जयपुर जैसे पर्यटन स्थलों को राजमार्ग से बहुत लाभ मिलेगा'।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान एवं देश की प्रगति के दो मज़बूत स्तंभ बनेगें और आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे।
- ये दोनों परियोजनाएँ मुंबई-दिल्ली आर्थिक गलियारे को मज़बूत करेंगी और सड़क एवं फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी भारत के कई इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और अन्य उद्योगों के लिये भी नए अवसर पैदा होंगे।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर, बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइनों को बिछाने की व्यवस्था की गई है और बची हुई भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ उसके भंडारण के लिये किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे 1,386 किमी. की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी को 1,424 किमी. से 12 प्रतिशत कम करके 1,242 किमी. कर देगा और यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे तक यानी 50 प्रतिशत कम हो जाएगा।

नोट :

- यह छह राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा।
- इस एक्सप्रेस-वे में 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अडन्नें और 8 मल्टी- मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के साथ-साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जेएनपीटी बंदरगाह जैसे नए बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी सेवा प्रदान करेगा।

डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का हुआ समापन

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी, 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान के समापन समारोह में विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- फोटोग्राफी वर्ग में 'जॉय ऑफ चाइल्डहुड 'विषय पर राजेश कुमार सोनी ने प्रथम पुरस्कार और उदय डंगायच ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तो वहीं 'रूरल राजस्थान 'विषय पर सिकंदर खान ने प्रथम एवं अविनाश मेहता ने दूसरा पुरस्कार हासिल किया।
- पॉप गायन में अनिल हासवानी को प्रथम तथा गोवर्धन को द्वितीय ,शास्त्रीय गायन में हुल्लास पुरोहित को प्रथम तथा ऐश्वर्य आर्य व मोहम्मद शोएब को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
- इसके अलावा भारतीय फिल्म संगीत की गायन श्रेणी में अलीना भारती को प्रथम एवं हर्ष कुमार गोला को द्वितीय पुरस्कार मिला।
- शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में राधिका अरोड़ा प्रथम व संगीता सैन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- लोकनृत्य में वैशाली सुरोलिया को पहला पुरस्कार मिला तो वहीं रुनझुन घोष को दूसरा पुरस्कार दिया गया।
- गौरतलब है कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र में 9 से 12 फरवरी,2023 तक डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि डेल्फिक खेलों की शुरुआत ग्रीस के डेल्फिक गाँव से हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चार बार इनका आयोजन हो चुका है तथा अब भारत के राज्यों में भी इनके आयोजन होने लगा है।

जयपुर में बनेगा 'हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर'

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी, 2023 को राजस्थान के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान, जयपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एच.पी.सी.आई.एल.) के बीच वातानुकूलित 'हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर 'की स्थापना के लिये एमओयू साइन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस हॉल का निर्माण नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने तथा विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये जयपुर के शास्त्री नगर में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान में किया जाएगा।
- 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस हॉल की लागत करीब 7 करोड़ रुपए होगी। हॉल के निर्माण में होने वाले व्यय में एन.पी.सी.आई.एल. की ओर से 4 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस केंद्र के निर्माण से आमजन को परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों एवं देश में इस क्षेत्र में किये गए अनुसंधान एवं विकास की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ निर्मित होने वाली गैलेरी में विभिन्न पैनलों, बैनरों, मॉडलों, प्लेकार्ड, कट-आउट, चल चित्रों, प्रश्नावलियों, खेलों, फिल्मों आदि के माध्यम से न्यूक्लियर पावर के बारे में जानकारी मिलेगी।
- इस एमओयू पर एन.पी.सी.आई.एल. की ओर से अधिशासी निदेशक एम. वेंकटाचलम और निगम संचार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संग्रहालयाध्यक्ष कैलाश मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारां ज़िले के ग्राम बडां में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा निर्मित श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर में बीमार तथा घायल पशु-पक्षियों को तत्काल उपचार मिल सकेगा, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ हमारे आस-पास रहने वाले जीवों का संरक्षण किया जा सकेगा।
- श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अस्पताल में समस्त उपचार सुविधाएँ 24 घंटे संचालित रहेंगी। यहाँ आस-पास के क्षेत्र में किसी भी पशु-पक्षी के बीमार, संक्रमित अथवा अन्य कारणों से प्रभावित होने की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाएगा।
- इस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार करेंगे। यहाँ जाँच केंद्र में पशु-पक्षियों के खून, गोबर आदि सभी प्रकार की जाँच के साथ-साथ एक्स-रे एवं सोनोग्राफी जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। अस्पताल परिसर में 3 ऑपरेशन थियेटर एवं 6 से अधिक आधुनिक सुविधायुक्त वार्ड हैं।
- इस अस्पताल में पशु-पक्षियों के लिये आउटडोर-इनडोर सहित संपूर्ण उपचार की सुविधाएँ हैं। प्रदेश में पहली बार पशु-पक्षियों के लिये अत्याधुनिक मशीनों के साथ इस प्रकार की सुविधाएँ स्थापित कर अनूठी पहल की गई है। यहां पशु-पक्षियों का ऑपरेशन, इलाज, आई. सी.यू. वार्ड तथा एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीव संरक्षण एवं पशु प्रेम की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिये निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसे अब विभाग का रूप दिया गया है।
- उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नंदीशाला की स्थापना के लिये लगभग 1.56 करोड़ रुपए तथा गौशाला की स्थापना के लिये लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। चारे की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए गौशालाओं की मांग पर 6 माह के स्थान पर 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी गौवंश तथा पशु संपदा के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। लंपी रोग से दुधारू गौवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 'मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना' के तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं के लिये 40-40 हज़ार रुपए का बीमा करवाया जाएगा। इस पर 750 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पशुओं के नि:शुल्क टीकाकरण तथा गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के लिये 1100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान बजट में किया गया है।

'साल एक : फैसले अनेक' पुस्तिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के कार्यकाल के सफल एक साल पूर्ण होने पर आरटीडीसी की उपलब्धियों, नीतिगत निर्णयों पर 'साल एक : फैसले अनेक'पुस्तिका का विमोचन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने होटल गणगौर में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तिका का विमोचन किया।
- पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आरटीडीसी प्रबंधन द्वारा शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' का पुन: संचालन, आरटीडीसी होटल के जीर्णोद्धार कार्य, हेलीकॉप्टर जॉयराइड जैसे कार्य किये हैं जो राजस्थान में पर्यटन के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

नोट :

- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पंद्रह सौ करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 लागू की गई है जिससे पर्यटन के क्षेत्र को नई दिशा मिली।
- इस अवसर पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आरटीडीसी द्वारा चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों के तहत होटल गणगौर के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया।
- आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि होटल गणगौर नवीनीकरण के कार्यों से अपने पुराने गौरव को हासिल करेगी एवं निजी होटल से प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार होगी।

राज्य भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को राजस्थान के भू-जल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा में बताया कि राज्य में भू-जल दोहन के नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भू-जल मंत्री डॉ. जोशी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
- उन्होंने बताया कि राज्य में भू-जल के समुचित उपयोग तथा राज्य के औद्योगिक इकाइयों के सुविधा हेतु भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बजट घोषणा की पालना में विभाग द्वारा ड्राफ्ट बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। विधि विभाग से प्राप्त सुझावों का समावेश कर ड्राफ्ट बिल वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में भू-जल दोहन की स्थिति चिंताजनक है तथा राज्य में 151 प्रतिशत दोहन हो रहा है। वर्तमान में भू-जल दोहन के संबंध में कोई भी निर्णय राज्य सरकार केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के आधार पर ही करती है।
- इससे पहले भू-जल मंत्री ने विधायक राजेंद्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि नीतिगत निर्णय की पालना में राज्य भू-जल विभाग प्रतिवर्ष नियमित रूप से सर्वे करता है तथा एक नियमित अंतराल के पश्चात् राज्य के भू-जल संसाधनो का आकलन किया जाता है।
- उन्होंने बताया कि इसी क्रम में केंद्रीय भू-जल बोर्ड व भू-जल विभाग द्वारा संयुक्त स्तर पर राज्य के भू-जल संसाधन की नवीनतम आकलन रिपोर्ट 2022 तैयार कर अंतरविभागीय राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमोदन कराकर जारी कर दी गई है।
- डॉ. जोशी ने बताया कि वर्तमान में भू-जल आंकलन की नवीनतम रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 के अनुसार राज्य के 295 ब्लॉक एवं सात शहरी क्षेत्रों में से 219 ब्लॉक को अतिदोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्द्धसंवेदनशील, 38 सुरक्षित में वर्गीकृत किया गया है। शेष 3 ब्लॉक में भू-जल लवणीय होने के कारण रिपोर्ट में इनका भू-जल आकलन नहीं किया गया है।
- उन्होंने सात शहरी क्षेत्र में सम्मिलित- अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

सांभर फेस्टिवल-2023

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को राजस्थान पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग द्वारा सांभर लेक पर 17 से 19 फरवरी तक सांभर फेस्टिवल-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग के द्वारा निरंतर नवाचार किये जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में प्रमुख मेलों और उत्सवों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग द्वारा सांभर फेस्टिवल-2023 का आयोजन करवाया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि अन्य मेलों और उत्सवों की तरह ही सांभर फेस्टिवल भी देशी-विदेशी पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

नोट :

- तीन दिवसीय सांभर फेस्टिवल में प्रतिदिन शाम को विभिन्न सेलिब्रिटी और प्रसिद्ध लोक कलाकार सांस्कृतिक संध्या में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियाँ देंगे।
- फेस्टिवल की शुरुआत एडवेंचर बाइक राइड से होगा। यह रैली जयपुर से प्रारंभ होकर सांभर झील कार्यक्रम स्थल पर खत्म होगी। स्टार नाइट गेजिंग इवेंट के तहत रात को पर्यटकों को सांभर के खुले आसमान में तारों को निहारने का मौका मिलेगा।
- फेस्टिवल के दौरान पतंगबाजी और कैमल राइड सहित पैरा सैलिंग, एटीवी राइड, मोटर साइकिल रैली जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।
- उपनिदेशक शेखावत ने बताया कि सांभर स्थित देवयानी कुंड पर दीपोत्सव और सेलिब्रिटी नाइट के आयोजन के साथ ही लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी सैलानियों के लिये आकर्षण का केंद्र रहेगी। सैलानियों को सांभर के ऐतिहासिक महत्त्व और परिंदों की रोचक जानकारियों से रूबरू करवाने के लिये टॉक शो का भी आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रभारी मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 को सदन में प्रस्तुत किया।
- उन्होंने बताया कि यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये लाया गया है।
- शांती कुमार धारीवाल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से 48 हज़ार 332 करोड़ 27 लाख 3 हज़ार रुपए की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी।

नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं श्री सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

17 फरवरी, 2023 को राज्य विधानसभा ने नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं श्री सांवलिया जी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने दोनों विधेयक चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत किये। सदन में विधेयकों पर हुई चर्चा के बाद देवस्थान मंत्री ने विधेयकों के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दोनों विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाए गए हैं।
- उन्होंने कहा कि इस संशोधन से पहले दोनों मंदिरों के बोर्ड में गूंगे, बहरे एवं कुष्ठ रोगी सदस्य नहीं बन सकते थे। उनके मन में इस कारण कुंठा होती थी। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक उनकी भावनाओं को सम्मान देने के साथ ही उनकी हीन भावना समाप्त करेंगे।
- मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि इन विधेयकों के पारित होने से अब गूंगे, बहरे एवं कुष्ठ रोगी भी इन मंदिरों के बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकेंगे तथा धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकेंगे।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की है। देवस्थान विभाग के माध्यम से कोरोना के दौरान मोक्ष-कलश योजना चलाई गई एवं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है।
- इससे पहले दोनों विधेयकों को सदस्यों द्वारा जनमत जानने के लिये प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया था।

नोट :

जयपुर के मशहूर सिटी पार्क में होगा 'रोज शो-2023' का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

17 फरवरी, 2023 को आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 26 फरवरी को जयपुर के मशहूर सिटी पार्क में 48वाँ 'रोज शो-2023' का आयोजन किया जाएगा।।

प्रमुख बिंदु

- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के साथ सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बैठक कर कार्यक्रम की कार्ययोजना को साझा किया। आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 48वाँ रोज शो में गुलाब की 500 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि सिटी पार्क में पूर्व में ही 'जयपुर फ्लावर शो'का एरिया विकसित किया गया था, जो कि लोगों में खासा आकर्षण बना हुआ है। सोसायटी द्वारा हर वर्ष फरवरी माह में होने वाला 'रोज शो'अब सिटी पार्क में ही आयोजित किया जाएगा, जोकि आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिये भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।
- सोसाइटी के संरक्षक एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाइटी द्वारा हर वर्ष सेंट्रल पार्क व यूथ हॉस्टल में रोज शो का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार शहर की धड़कन बन चुके सिटी पार्क में यह भव्य शो आयोजित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि शो में आमजन भी उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ हिस्सा ले सकते हैं। अच्छे गुलाबों की किस्मों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन सहित कई अन्य रचनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

17 फरवरी, 2023 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये हैं। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल-2022 (संवत् 2079) नियमित / विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिये इन ज़िलों के गाँव के लिये अधिसूचना जारी की गई है।
- आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बारां ज़िले के 1231 ग्राम, भरतपुर के 957, बूंदी के 517, धौलपुर के 58, श्रीगंगानगर के 02, झालावाड़ के 1597, करौली के 13, नागौर के 347, सवाई माधोपुर के 14, टोंक के 716, कोटा के 766, बांसवाड़ा के 717, प्रतापगढ़ के 625, जोधपुर के 47, अजमेर के 227 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-3 का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जोधपुर ज़िले के उम्मेद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की 'राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना' का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण को पूरा करने में वित्तीय कमी नहीं आने दी जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2054 की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी।

नोट :

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि तृतीय चरण में मुख्य नहर के समानांतर संपूर्ण लंबाई में पाइप लाइन व चार पंपगृहों की प्रस्तावित योजना को पूर्ण कराया जाना है। कार्य पूर्ण हो जाने पर वर्तमान राजीव गांधी लिफ्ट नहर व प्रस्तावित पाइप लाइन द्वारा सम्मिलित रूप से कुल 1030 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी।
- इससे जोधपुर शहर के साथ ही फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा, भोपालगढ़ व समदड़ी कस्बे तथा जोधपुर ज़िले के 1 हज़ार 830 गाँव, बाड़मेर के 211 गाँव और पाली के 126 गाँवों को मिलाकर कुल 2 हज़ार 167 गाँवों की वर्ष 2054 की लगभग 80 लाख अभिकल्पित जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सकेगा। इससे79 करोड़ लीटर से अधिक प्रतिदिन की शुद्ध पेयजल मांग पूरी की जाएगी।
- तृतीय चरण पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी नहर से जल आहरण क्षमता बढ़कर 420 क्यूसेक हो जाएगी। परियोजना से जोधपुर ज़िले के अंतर्गत संस्थागत एवं व्यापारिक क्षेत्र की पेयजल मांग93 करोड़ लीटर प्रतिदिन, रक्षा विभाग के लिये 3.72 करोड़ लीटर प्रतिदिन, औद्योगिक (रीको) क्षेत्र के लिये 4.30 करोड़ लीटर प्रतिदिन तथा रोहट में विकसित हो रहे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 6 करोड़ लीटर पेयजल की प्रतिदिन पूर्ति हो सकेगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता के लिये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अति आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसके लिये 13 हज़ार 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

मुख्यमंत्री ने किया व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जोधपुर ज़िले में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिये चिकित्सा क्षेत्र में हरसंभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जोधपुर में हर क्षेत्र में विकास कार्यों पर पूरा ध्यान रखा है। जोधपुर में संभवत: सभी प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हैं। यहाँ एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोले गए हैं।
- उन्होंने बताया कि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं दिव्यांगजनों के लिये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है।

पवन अरोड़ा 'विजनरी लीडर' और 'ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीरडरशिप' अवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा को मुंबई में टाइम्स समूह की वर्ल्ड एचआरडी कॉन्ग्रेस ने प्रतिष्ठित 'विजनरी लीडर' और प्रतिष्ठित वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने 'ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप' अवार्ड से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा की ओर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त जेएस बुगालिया और डॉ. दिलीप शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- गौरतलब है आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा के नेतृत्व में राजस्थान आवासन मंडल देशभर के मैनेजमेंट गुरूओं के लिये केस स्टडी बना हुआ है। देश के कई राज्य इस मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।
- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 12 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डवेलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड'जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

नोट :

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की नई वेबसाइट लांच

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी भगत ने राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण की नई एवं अपडेटेड वेबसाइट को लांच किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा राज्य के कार्मिकों की सेवा संबंधी वादों की सुनवाई की जाती है। आमजन को राजस्थान सरकार द्वारा त्वरित न्याय एवं पारदर्शिता के साथ सूचनाओं के संप्रेषण के लिये इस वेबसाइट को लांच किया गया है।
- अधिकरण के रजिस्ट्रार पंकज ओझा ने बताया कि वेबसाइट को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- इस वेबसाइट में एसएमएस के माध्यम से अलर्ट की सुविधा, जोधपुर बेंच के केसेज का ऑनलाइन इंद्राज करना, सभी प्रकार के स्टे एवं निर्णय अपलोड करने की सुविधा, वाद सूची को केस परपज के अनुसार बेंचों में विभाजन, अधिवक्ताओं की सूचना, केस री-ओपन की सुविधा, केस लिंक एवं टैग करने की सुविधा, रोस्टर संधारण की सुविधा, एमआईएस तैयार करने की सुविधाएँ एवं एक से अधिक प्राइवेट पार्टी की एंट्री जैसी सुविधाएँ सम्मिलित की गईं हैं।

सीकर के दरीबा में बेसमेटल व हनुमानगढ़ के सतीपुरा क्षेत्र में मिले पोटाश के भंडार

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को राजस्थान के माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान सीकर ज़िले के दरीबा में खनिज बेसमेटल के भंडार मिले हैं और हनुमानगढ़ जिले के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुनजा नार्थ ब्लॉक में पोटाश के भंडार मिले हैं।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जीएसआई ने सीकर क्षेत्र में जी 2 स्तर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में जी 3 स्तर की खोज पूरी कर ली है जिससे इन क्षेत्रों में नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर अब खनन लीज के लिये ऑक्शन की कार्यवाही की जा सकती है।
- उन्होंने बताया कि जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार सीकर ज़िले के दरीबा ब्लॉक में जी 2 स्तर के एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरुप 33 प्रतिशत कॉपर बेसमेटल के 2.81 मिलियन टन भंडार होने की संभावना है तो दूसरी और नागौर-गंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ के सतीपुरा सब बेसिन में जी 3 के एक्सप्लोरेशन के परिणामस्वरुप खनिज पोटाश के करीब 340 मिलियन टन के भंडार मिले हैं।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि समयवद्ध कार्ययोजना बनाकर इन ब्लॉकों के ऑक्शन की आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से पूरी की जाए ताकि बेसमेटल व पोटाश जैसे बहुमूल्य खनिजों का दोहन हो सके, विदेशों से आयात पर निर्भरता कम हो और प्रदेश की राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।
- उल्लेखनीय है कि एसीएस माइंस को राज्य व केंद्र सरकार के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उपमहानिदेशक रामजीवन ने एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट दी।
- जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उपमहानिदेशक रामजीवन ने बताया कि प्रदेश में खनिज खोज कार्य खनिज विभाग के साथ ही केंद्र सरकार के जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम सहित संस्थाओं द्वारा एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है।

जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एमओयू पर किये गए हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित शासन सचिवालय परिसर में आयोजित बैठक में जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच हुए एमओयू के तहत अमृतसर-भटिंडा-जामनगर एक्सप्रेसवे पर राज्य में तीन ज़िलों हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के कुल छह स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किये जाएंगे।
- कुल 27.43 मेगावाट क्षमता के ये पावर प्लांट सौर कृषि आजीविका योजना (पीएम कुसुम) के तहत लगाए जाएंगे। ये पावर प्लांट हनुमानगढ़ ज़िले के कोल्हा गाँव, बीकानेर ज़िले के मलकीसर-गोपल्यान रोड, नौरंगदेसर एवं रासीसर गाँव तथा जोधपुर ज़िले के भीकमकोर गाँव में लगेंगे तथा 8 सबस्टेशन को कवर करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से यह कार्य योजना तैयार की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस हाइवेज के किनारे सौलर पैनल लगाए जाने हैं। यह योजना पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर विकसित की जाएगी।

राष्ट्रपति ने राजस्थान के मूकाभिनय कलाकार विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी विलास जानवे को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर देश के 128 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार के रूप में विलास जानवे को ताम्र पत्र, एक लाख रुपए एवं अंगवस्त्र प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि 68 वर्षीय विलास जानवे पिछले पाँच दशकों से मूकाभिनय से जुड़े हैं। इन्हें संस्कृति मंत्रालय से मूकाभिनय के क्षेत्र में 2001 में सीनियर फेलोशिप भी मिल चुकी है।
- मूकाभिनय में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे देश के पाँचवें कलाकार हैं। इससे पूर्व यह पुरस्कार प. बंगाल के गुरु योगेश दत्ता, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, असम के मोइनुल हक और त्रिपुरा के सपन नंदी को मिल चुका है।
- विदित है कि विलास जानवे ने 1998 से शुरू राष्ट्रीय मूकाभिनय उत्सवों में पत्नी किरण जानवे के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान की कला अकादमियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिये मूकाभिनय की कार्यशालाएँ निर्देशित की हैं।
- अपने गुरु पद्मश्री निरंजन गोस्वामी को मूकाभिनय की कार्यशालाओं में सहायता करने के साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक विषयों पर कई मूकाभिनयों की संरचना की है। देश के कई मंचों पर भी वे अपनी इस कला का प्रदर्शन कर चुके हैं।
- उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में 28 वर्ष तक कार्यक्रम अधिकारी रहे जानवे ने सी.सी.आर.टी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने सेंट्रल जेल, उदयपुर में मूकाभिनय का प्रशिक्षण भी दिया है।
- विलास जानवे ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार रचना 'गीतांजली' की कविताओं पर भी मूकाभिनय कर नवाचार किया है।

शहरों में रोज़गार गारंटी योजना का बढ़ा दायरा

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरों में हर हाथ को रोज़गार और बेरोज़गारों को संबल प्रदान करने के लिये 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोज़गार देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू की गई थी। गत वर्ष योजनांतर्गत प्रति परिवार 100 दिवस का रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के अनुमोदित दिशा-निर्देशों में संशोधन की सहमति दे दी है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। शहरी बेरोज़गारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध कराने से लगभग 1100 करोड़ रुपए का व्यय होना संभावित है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। इस योजना में अब प्रति परिवार 125 दिवस का रोज़गार मिलेगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं शताब्दी में निर्मित जयपुर स्थित खानिया की बावड़ी से 9 सितंबर, 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया था।
- योजना में जरूरतमंद परिवार जन आधार कार्ड के माध्यम से जॉब कार्ड बनवाकर रोज़गार की मांग कर सकते हैं। शहरी बेरोज़गारों को रोज़गार की गारंटी प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा बेरोज़गारी के विरूद्ध यह योजना संचालित की गई है।
- इस योजना में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हैरिटेज संरक्षण, स्वच्छता, सेवा, कन्वर्जेंस तथा संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्यों सहित अन्य कई तरह के कार्य अनुमत किये गए हैं।
- योजना के महत्त्वपूर्ण बिंदु-
  - 51 लाख से अधिक जॉब कार्ड अब तक बनाए गए।
  - 94 लाख से अधिक सदस्य अब तक योजना से जुड़े।
  - 09 लाख परिवारों द्वारा अब तक रोज़गार की मांग की गई।
  - 13 लाख से अधिक ऑनलाइन मस्टररोल जारी।
  - 259 रुपए अकुशल श्रमिक की प्रति दिवस मजदूरी।
  - 271 रुपए अर्द्धकुशल श्रमिक/मेट की प्रति दिवस मजदूरी।
  - 283 रुपए कुशल श्रमिक की प्रति दिवस मजदूरी।
  - 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति कर सकते हैं कार्य।
  - ई-मित्र से भी जन आधार कार्ड के जरिये नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा।

विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकारों एवं योजनाओं की जाँच हेतु स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान शुरू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जाँच के लिये स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान आरंभ किया किया है। इनके नेतृत्व में अभियान की शुरुआत प्रदेश के उदयपुर ज़िले से हुई।

प्रमुख बिंदु

- विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उदयपुर शहर के 3 स्कूलों के निरीक्षण के साथ इसकी शुरुआत हुई।
- सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के भवनों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान देखा जा रहा है कि विशेष योग्यजन बच्चों के लिये स्कूलों के भवन एवं व्यवस्थाएँ कितने अनुकूल हैं।

नोट :

- इसके तहत स्कूलों के कक्षा कक्ष परिसर, शौचालय, कैफेटेरिया, बैठने की व्यवस्था, प्रवेश द्वार, लिफ्ट, पेयजल, आपातकाल निकासी एवं रैंप की व्यवस्था सहित 75 पैरामीटर की गहनता से जाँच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन को विशेष योग्यजन बच्चों का पूरा ख्याल रखने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
- उमाशंकर शर्मा ने बताया कि जाँच के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत विद्यालयों में विशेष योग्यजन बच्चों के प्रवेश की भी जाँच की जा रही है एवं विद्यालयों को इस अधिनियम के तहत नियमानुसार विशेष योग्यजन बच्चों को प्रवेश देने हेतु पाबंद किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि उदयपुर में मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी विद्यालयों की जाँच के आदेश दे दिये गए हैं। आदेश के अनुसार ज़िले के सभी पीईईओ को अपने अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण करना है। जो विद्यालय विशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल नहीं पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस अभियान का उद्देश्य राज्य के समस्त विद्यालयों को विशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाना है जिससे कि वे भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सक्षम नागरिक बन सकें।
- विशेष योग्यजन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत हर विद्यालय को विशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान को मिला बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवॉर्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवॉर्ड के लिये चुना गया।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विभिन्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को इस अवॉर्ड के लिये चुना गया है।
- देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान की उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिये मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है।
- कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह अवॉर्ड पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को प्रदान किया।

'रोज़ शो-2023'

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हॉट डेस्टिनेशन बन चुके सिटी पार्क में द रोज़ सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें 'रोज़ शो-2023' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि देश-दुनिया में मशहूर हो चुका सिटी पार्क 400 किस्म के गुलाबों की खुशबू से गुलज़ार रहा। द रोज़ सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित 48वाँ रोज़ शो ने न केवल स्थानीय बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया।
- उन्होंने बताया कि आमजन में सिटी पार्क की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोसायटी ने फरवरी माह में आयोजित होने वाले 'रोज़ शो' को हर वर्ष सिटी पार्क में ही आयोजित करने का फैसला किया है।
- 'रोज़ शो-2023' में आमजनों ने भी उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ हिस्सा लिया। अच्छे गुलाबों की किस्मों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पेंटिंग कंपीटीशन सहित कई अन्य रचनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गए।

नोट :

- प्रदर्शनी में नीलकमल, ट्यूलिप, होम गार्डन नर्सरी द्वारा विभिन्न प्लांट्स का भी प्रदर्शन किया गया। शो में ग्रुप 1 से 3 में 400 से ज्यादा किस्म के रंग-बिरंगे गुलाबों का प्रदर्शन किया गया तथा बेहतरीन किस्म के गुलाब के लिये सम्मानित भी किया गया।
- कार्यक्रम में एंपरर ऑफ द शो का पुरस्कार सचिव जेडीए, एंप्रेस ऑफ द शो माया बालान, किंग ऑफ द शो रामचंद्र सैनी, क्वीन ऑफ द शो सचिव जेडीए, प्रिंस ऑफ द शो रामलाल, प्रिंसेस ऑफ द शो माया बालान एवं बेस्ट एक्जिबिटर ऑफ द शो होटल रामबाग पैलेस को दिया गया।

'रोज़ शो-2023'

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हॉट डेस्टिनेशन बन चुके सिटी पार्क में द रोज़ सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें 'रोज़ शो-2023' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि देश-दुनिया में मशहूर हो चुका सिटी पार्क 400 किस्म के गुलाबों की खुशबू से गुलज़ार रहा। द रोज़ सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित 48वाँ रोज़ शो ने न केवल स्थानीय बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया।
- उन्होंने बताया कि आमजन में सिटी पार्क की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोसायटी ने फरवरी माह में आयोजित होने वाले 'रोज़ शो' को हर वर्ष सिटी पार्क में ही आयोजित करने का फैसला किया है।
- 'रोज़ शो-2023' में आमजनों ने भी उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ हिस्सा लिया। अच्छे गुलाबों की किस्मों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पेंटिंग कंपीटीशन सहित कई अन्य रचनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गए।
- प्रदर्शनी में नीलकमल, ट्यूलिप, होम गार्डन नर्सरी द्वारा विभिन्न प्लांट्स का भी प्रदर्शन किया गया। शो में ग्रुप 1 से 3 में 400 से ज्यादा किस्म के रंग-बिरंगे गुलाबों का प्रदर्शन किया गया तथा बेहतरीन किस्म के गुलाब के लिये सम्मानित भी किया गया।
- कार्यक्रम में एंपरर ऑफ द शो का पुरस्कार सचिव जेडीए, एंप्रेस ऑफ द शो माया बालान, किंग ऑफ द शो रामचंद्र सैनी, क्वीन ऑफ द शो सचिव जेडीए, प्रिंस ऑफ द शो रामलाल, प्रिंसेस ऑफ द शो माया बालान एवं बेस्ट एक्जिबिटर ऑफ द शो होटल रामबाग पैलेस को दिया गया।

नोट :